पेसा अधिनियम 1996 की मुख्य विशेषताएं:

1. ग्राम सभा को विशिष्ट शक्तियां-

प्रत्येक गांव की अपनी ग्राम सभा होगी। एक गांव में एक या एक से अधिक बस्तियां या एक समुदाय वाले छोटे गांव होंगे और परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार अपने मामलों का प्रबंधन करेगें।
[पेसा अधिनियम की धारा 4 (ख) और 4 (ग)

(भाग IX में, ग्राम पंचायत के सभी निर्वाचक एक ग्राम सभा का गठन करते हैं)

2. ग्राम सभा निम्नलिखित की सुरक्षा और संरक्षण के लिए "सक्षम" है-

(क) लोगों की परंपराएं और रीति-रिवाज, और उनकी सांस्कृतिक पहचान,

(ख) सामुदायिक संसाधन, और

(ग) विवाद समाधान का प्रथागत तरीका।

[पेसा अधिनियम की धारा 4 (घ)]

3. ग्राम सभा के अनिवार्य कार्यकारी कार्य हैं-

(क) सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं की मंजूरी देना। [पेसा अधिनियम की धारा 4 (ङ) (i)

(ख) गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान करना। [पेसा अधिनियम की धारा 4 (ङ) (ii)

(ग) योजनाओं के लिए पंचायत द्वारा धन के उपयोग का प्रमाणपत्र जारी करना; पेसा अधिनियम की धारा 4 (ङ) में निर्दिष्ट कार्यक्रम और परियोजनाएं [पेसा अधिनियम की धारा 4 (च)]

4. उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा/पंचायत को विशिष्ट शक्तियां-

(क) विस्थापित व्यक्तियों के भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन और पुनर्वास में अनिवार्य परामर्श का अधिकार। [पेसा अधिनियम की धारा 4 (झ)

(ख) उपयुक्त स्तर पर पंचायत को लघु जल निकायों की योजना और प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है। [पेसा अधिनियम की धारा 4 (ञ)]

(ग) गौण खनिजों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस, खनन पट्टे, रियायतें प्रदान करने से पूर्व उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायत द्वारा अनिवार्य अनुशंसाएं। [पेसा अधिनियम की धारा 4 (ट) और 4 (ठ)]

5. ग्राम सभा और पंचायत को उचित स्तर पर प्रदान की गई शक्तियां-

(क) नशीले पदार्थों की बिक्री/खपत को विनियमित करना। [पेसा अधिनियम की धारा 4(ड)(i)

(ख) लघु वनोपज का स्वामित्व। [पेसा अधिनियम की धारा 4 (ड) (ii)

(ग) भूमि अलगाव की रोकथाम और अलग-थलग पड़ी भूमि को बहाल करना। [पेसा अधिनियम की धारा 4 (ड) (iii)

(घ) गांव के बाजारों का प्रबंधन करना। [पेसा अधिनियम की धारा 4 (ड) (iv)

(ङ) अनुसूचित जनजातियों के ऋण पर नियंत्रण करना [पेसा अधिनियम की धारा 4 (ड) (v)]

(च) सामाजिक क्षेत्र में संस्थानों और कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण, जनजातीय उप योजनाओं और संसाधनों सहित स्थानीय योजनाएं [पेसा अधिनियम की धारा 4 (ड) (vi) और 4 (ड) (vii)]

***